

II समग्र मांग *

2011-12 में समग्र मांग के अधिकांश घटक धीमे पड़ गये। समग्र पूंजी निर्माण के साथ-साथ कंपनियों की निवेश इच्छाओं में यथा परिलक्षित निवेश कम होता गया और 2012-13 में उसमें मंद गति से सुधार की शुरूआत होने की संभावना है। निवल निर्यात मांग में गिरावट आई जो वैश्विक धीमेपन की परिचायक है। किंतु, तेल के अधिक मूल्यों ने उच्च ईंधन सब्सिडी के कारण सरकार के राजकोषीय आंकड़ों को प्रभावित किया और मूल्य समायोजन के अभाव में 2011-12 में समग्र मांग में बढ़ोतरी की। जहाँ 2012-13 के केन्द्रीय बजट में सब्सिडियों को सीमित करने की प्रतिबद्धता की प्रतिज्ञा की गई, वहीं राजकोषीय घाटे के आंकड़ों में कोई भी गिरावट मांग प्रबंधन को प्रभावित करेगी और निवेश को पुनर्जीवित करने के मार्ग में बाधा बनेगी।

निवल निर्यात के साथ निवेश में गिरावट से मांग घटती है

II.1 अप्रैल-दिसंबर 2011 के दौरान अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण घट गया। यह आंशिक रूप से मुद्रास्फीति को रोकने वाली मौद्रिक

नीति के रुख का पश्च प्रभाव दर्शाता है। निवल निर्यात में भी, विशेष रूप से तिः में कमी आई जो प्रतिकूल आधार प्रभाव के साथ-साथ रुपये में गिरावट के कारण आयातों पर उच्चतर बहिर्गमन दर्शाती है (सारणी II.1)। 2011-12 के लिये व्यय-पक्षीय वृद्धि दरों के अग्रिम अनुमानों के मद्देनजर 2011-12 की तिः.4 के दौरान निजी उपभोग व्यय की अंतर्निहित वृद्धि दरें और सकल स्थिर पूंजी निर्माण, पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि पर प्रखर बढ़ोतरी दर्शाते हैं। जहाँ मुद्रास्फीति में गिरावट आने और साथ ही कुछ राज्यों में चुनाव संबंधी खर्चों से उपभोग को लाभ होगा, वहीं निवेश में अधिकांशतः आधार प्रभाव के कारण सुधार आयेगा। इससे तिः में वृद्धि का न्यूनतम स्तर तक पहुँचना स्पष्ट होता है।

बचत और निवेश दरों में गिरावट चिंता का कारण है

II.2 2010-11 में निवेश और बचत दोनों की दरों में कमी आई। 2010-11 में समग्र बचत दरों में गिरावट घरेलू और निजी कंपनी

सारणी II.1: व्यय पक्षीय जीडीपी (2004-05 मूल्य)

मद	2010-11 त्व.अ.	2011-12 अ.अ.	2010-11				2011-12			2010-11 अप्रै - दिसं	2011-12 अप्रै - दिस	
			तिः1	तिः2	तिः3	तिः4	तिः1	तिः2	तिः3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
वृद्धि दर												
बाजार दरों पर वास्तविक जीडीपी	9.6	7.5	9.5	8.9	10.1	7.7	8.5	6.7	6.3	9.5	7.1	
कुल उपभोग व्यय	8.1	6.0	9.6	9.2	7.1	7.5	5.5	3.4	5.9	8.6	5.0	
(i) निजी	8.1	6.5	9.3	8.7	7.6	8.0	5.9	2.9	6.2	8.5	5.1	
(ii) सरकारी	7.8	3.9	11.1	12.2	4.7	4.9	2.9	6.1	4.4	8.8	4.4	
सकल स्थिर पूंजी निर्माण	7.5	5.6	8.8	6.9	11.1	0.4	4.9	-4.0	-1.2	8.9	-0.2	
स्टॉक में परिवर्तन	37.4	2.9	39.4	35.5	37.7	4.6	1.8	-4.7	-0.4	37.5	-1.1	
निवल निर्यात	5.5	-30.1	-40.8	-10.1	18.6	34.8	-14.3	38.5	-33.0	-6.6	-1.6	
तुलनात्मक हिस्सा												
कुल उपभोग व्यय	70.1	69.1	73.0	72.4	72.9	63.1	70.9	70.1	72.6	72.7	71.3	
(i) निजी	58.7	58.1	62.0	61.7	60.4	52.6	60.5	59.5	60.4	61.4	60.2	
(ii) सरकारी	11.4	11.0	11.0	10.6	12.5	10.5	10.4	10.6	12.2	11.4	11.1	
सकल स्थिर पूंजी निर्माण	32.5	31.9	32.2	34.0	32.3	32.1	31.2	30.5	30.0	32.8	30.6	
स्टॉक में परिवर्तन	3.7	3.5	3.7	3.8	3.5	3.4	3.5	3.4	3.3	3.7	3.4	
निवल निर्यात	-6.0	-7.3	-7.9	-7.9	-6.3	-3.9	-8.4	-4.6	-7.8	-7.3	-7.0	
जापन:												बिलियन ₹
बाजार दरों पर वास्तविक जीडीपी	52,368	56,277	12,088	12,268	13,538	14,693	13,120	13,093	14,389	37,894	40,602	
त्व.अ. : त्वरित अनुमान। अ.अ. : अग्रिम अनुमान												
नोट: सारणी में केवल मुख्य मदें ही शामिल की गई हैं जिससे आंकड़ों का जोड़ 100 नहीं हो पायेगा।												
स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन।												

* चिर-परिचित सीमाओं के बावजूद, व्यय-पक्षीय जीडीपी आंकड़े समग्र मांग के घटकों के लिए प्रतिनिधि की भाँति प्रयुक्त हो रहे हैं।

सारणी II.2: सकल घरेलू बचत और सकल घरेलू पूँजी निर्माण

(जीडीपी का प्रतिशत वर्तमान बाजार मूल्यों पर)

मद	2008-09	2009-10	2010-11 त्व.अ
1	2	3	4
1. सकल घरेलू बचत	32.0	33.8	32.3
1.1 घरेलू क्षेत्र	23.6	25.4	22.8
i) वित्तीय बचत	10.1	12.9	10.0
ii) भौतिक आस्तियों में बचत	13.5	12.4	12.8
1.2 निजी कंपनी क्षेत्र	7.4	8.2	7.9
1.3 सार्वजनिक क्षेत्र	1.0	0.2	1.7
2. सकल घरेलू पूँजी निर्माण *	34.3	36.6	35.1
2.1 घरेलू क्षेत्र	13.5	12.4	12.8
2.2 निजी कंपनी क्षेत्र	11.3	12.7	12.1
2.3 सार्वजनिक क्षेत्र	9.4	9.2	8.8

* गुटियों और कमियों के लिये समायोजित।

त्व.अ : त्वरित अनुमान।

क्षेत्र दोनों के कारण हुई जिसने सार्वजनिक क्षेत्र की बचत दरों में सुधार को बहुत ज्यादा नकार दिया। 2010-11 में घरेलू क्षेत्र की बचत दरों में, 2009-10 की कीर्तिमान ऊँचाई को छू लेने के बाद, गिरावट आई। घरेलू बचतों में भी जहाँ वित्तीय बचत दरों में तीव्र गिरावट आई वहीं 2010-11 में भौतिक बचत दर में वृद्धि हुई। निवल वित्तीय बचत दरों में गिरावट बैंक जमाराशियों और जीवन बीमा में घरेलू बचतों की धीमी वृद्धि के साथ ही शेयरों और डिबेंचरों में निवेश में पूर्ण गिरावट जो मुख्य रूप से म्यूचुअल फंड इकाइयों के उन्मोचन से प्रेरित था, के कारण आई। फिर भी, वर्ष के दौरान छोटी बचतों और मुद्रा के पक्ष में द्विकाव बना रहा।

II.3 2010-11 में सकल देशी पूँजी निर्माण (निवेश) की दर में गिरावट निजी कंपनी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र की निवेश दरों

में गिरावट के कारण आई जबकि घरेलू निवेश दर में वृद्धि हुई। अवसंरचना (इंफ्रास्ट्रक्चर) विकास की भारी मांग के साथ-साथ पेट्रोलियम शोधन जैसे क्षेत्रों की क्षमताओं पर अत्यंत दबाव के चलते, अर्थव्यवस्था में निर्माण और मशीनों तथा उपस्करों दोनों में पूँजी निर्माण की दर बढ़ाने की नितांत आवश्यकता है। आगे, उच्च वृद्धि दर की मध्य-अवधि तक पुनर्प्राप्ति और उसे बनाये रखने की क्षमता बचत और निवेश दरों में बढ़ोतरी के अलावा उत्पादकता में सुधारों पर निर्भर है।

कंपनी निवेश मंद बना रहा

II.4 कंपनी निवेशों में कमी आई और नये निवेश भी मंद बने रहे। अतः, 2012-13 निवेश में धीमी गति से पुनर्जीवित होने की संभावना है। विभिन्न वर्षों में परियोजनाओं के लिये स्वीकृत संस्थागत सहायता के ब्यारों के समयबद्ध विश्लेषण से पता चलता है कि 2011-12 में निजी कंपनी (गैर-वित्तीय) क्षेत्र द्वारा किया गया इच्छित पूँजी व्यय पिछले वर्ष की तुलना में कम रहने की संभावना है (सारणी II.3)। अन्य कारकों समेत, उच्चतर ब्याज दरों और बढ़ते निविष्टि मूल्यों से निवेश भावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

II.5 पूँजी निर्माण की गति में धीमापन प्रमुख बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा परियोजनाओं के लिये स्वीकृत वित्त की संख्या/परिव्यय में तीव्र गिरावट से स्पष्ट है। 2010-11 की ति-3 में जो गिरावट शुरू हुई वह 2011-12 की ति.3 में बनी रही (सारणी II.4)। परिव्यय/परियोजनाओं, जिनके लिये वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई थी, में गिरावट विशेष रूप से ‘धातु और धातु उत्पाद’ और ‘ऊर्जा उद्योगों’ में सर्वाधिक रही थी (चार्ट II.1)।

सारणी II.3: बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत सहायता वाली परियोजनाओं के पूँजी व्यय के चरण

(बिलियन ₹)

वर्ष में पूँजी व्यय →	2007-08 तक	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 के बाद	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
स्वीकृति का वर्ष ↓								
2007-08 तक	1,826	1,317	583	376	98	47	—	4,247
2008-09	265	1,029	864	568	366	84	46	3,223
2009-10	2	448	1,494	1,282	853	365	116	4,560
2010-11	-	3	373	1,262	1,294	979	691	4,602
2011-12*	-	-	14	154	527	419	437	1,551
कुल योग #	2,093	2,797	3,328	3,642	3,138	1,894	1,290	-

*: 2011-12 ति.3 तक आंकड़े उपलब्ध

#. अनुमान प्रत्याशित हैं जिसमें केवल परिकल्पित निवेश को शामिल किया गया है और इस प्रकार वास्तविकता में प्राप्त/प्रयुक्त से भिन्न हैं।

सारणी II.4: संस्थागत सहायता प्रदत्त परियोजनाएं और उनकी परिकल्पित लागत (तिमाही-वार)

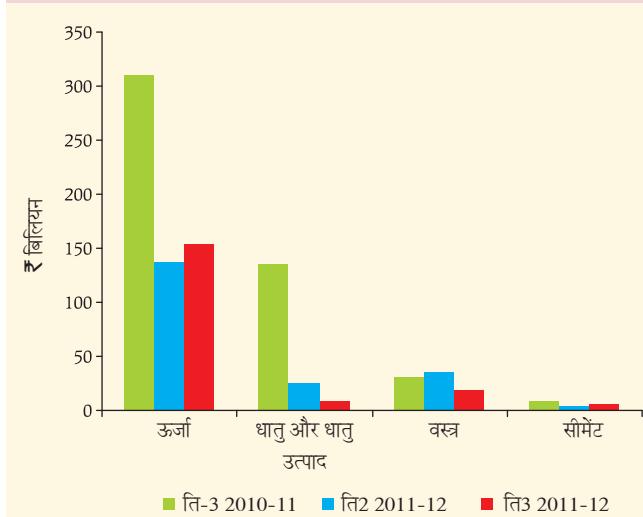
अवधि	परियोजनाओं की संख्या *	परियोजना लागत (बिलियन ₹)	
1	2	3	
2010-11	तिः 1 तिः 2 तिः 3 तिः 4	199 239 173 (166) 185	1,431 1,508 801 (795) 864
2011-12#	तिः 1 तिः 2 तिः 3**	144 176 (172) 124	880 363 (361) 310

* : 39 बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिये गये आंकड़ों पर आधारित।

** : 2011-12 की तिः 3 के लिये आंकड़े 34 बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिये गये आंकड़ों पर आधारित। 2010-11 की तिः 3 और 2011-12 की तिः 2 के लिये तद्रूप आंकड़े कोष्टकों में दिये गये हैं।

: 2011-12 के लिये आंकड़े अनन्तिम हैं।

चार्ट II.1: उद्योगवार निवेश की मंशा (राशि द्वारा)



लाभार्जन उच्च ब्याज दरों और बढ़ती निविष्टि लागतों से कंपनी लाभार्जन क्षमता प्रभावित हुई

II.6 जहाँ 2011-12 की तिः 3 के दौरान विक्रय लगातार सुदृढ़ बने रहे और वर्ष-दर-वर्ष और तिः-दर-तिः दोनों ही आधारों पर उच्चतर

वृद्धि दर दर्ज की, परिचालन लाभ और निवल लाभ में गिरावट आई क्योंकि व्यय और ब्याज लागत काफी बढ़ गयी (सारणी II.5)

सारणी II.5: कंपनी क्षेत्र-वित्तीय निष्पादन

मद	सामान्य कंपनियां (वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि प्रतिशत में)						
	2010-11				2011-12		
	तिः 1	तिः 2	तिः 3	तिः 4	तिः 1	तिः 2	तिः 3
1	2	3	4	5	6	7	8
कंपनियों की संख्या	2,352						
बिक्री	24.7	18.9	17.6	20.6	22.6	19.3	19.4
स्टॉक में परिवर्तन	411.6	-45.5	110.1	131.5	-39.4	-2.9	88.0
व्यय	29.1	20.1	19.6	22.7	23.0	22.8	24.9
जिसमें कच्चा माल	37.1	21.6	20.9	25.3	27.9	23.6	25.6
स्टाफ लागत	16.4	20.4	21.2	19.8	20.1	17.7	19.0
ऊर्जा एवं ईंधन	17.7	13.0	19.6	26.6	27.1	26.0	30.2
परिचालन लाभ (पीबीडीआईटी)	15.4	7.3	11.1	16.6	12.5	-0.9	-5.7
अन्य आय*	-21.5	58.7	6.3	-15.3	39.6	25.9	69.3
मूल्य-हास	20.1	17.5	14.7	15.2	9.8	9.8	10.4
सकल लाभ (पीबीआईटी)	8.9	9.5	9.7	11.6	16.1	-0.1	-2.5
ब्याज	27.4	6.2	23	31.2	22.1	47.6	42.8
कर ग्रावधान	6.2	10.0	6.5	2.2	21.6	3.8	-2.4
निवल लाभ (गैर परिचालन लाभ से पहले)	4.5	10.4	7.0	9.6	12.3	-16.3	-16.7
निवल लाभ (पीएटी)	3.7	9.1	9.4	13.6	6.7	-15.4	-31.0
प्रतिशत में अनुपात							
बिक्री की तुलना में स्टॉक में परिवर्तन #	2.5	0.8	1.3	2.3	1.2	0.5	2.2
बिक्री की तुलना में ब्याज	2.8	2.6	2.6	2.5	2.8	3.2	3.1
ब्याज भार	20.7	19.2	19.6	18.6	21.7	28.6	28.5
ब्याज व्याप्ति	4.8	5.2	5.1	5.4	4.6	3.5	3.5
बिक्री की तुलना में पीबीडीआईटी	16.2	15.4	15.9	15.3	14.9	12.8	12.5
बिक्री की तुलना में पीबीआईटी	13.7	13.5	13.5	13.4	13.0	11.3	11.0
बिक्री की तुलना में पीएटी	8.6	8.6	8.4	8.6	7.5	6.1	4.8
पीएटी की तुलना में अन्य आय	16.4	21.7	15.9	19.9	21.4	32.3	39.6

#: इस मद को सुनिश्चितता से रिपोर्ट करने वाली कंपनियों के लिये। *: अन्य आय में असामान्य आय/व्यय शामिल नहीं है, यदि सुनिश्चितता के साथ रिपोर्ट किया गया हो।

नोट: एक ही सेट की कंपनियों के लिये वृद्धि दरें संदर्भाधीन अवधि के लिये पछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के स्तर पर प्रतिशत परिवर्तन हैं।

सारणी II.6: कंपनी क्षेत्र-वित्तीय निष्पादन - क्रमवार

मद	सामान्य कंपनियां (ति-दर-ति वृद्धि प्रतिशत में)						
	2009-10 की ति-4 की तुलना में ति-1: 2010-11	2010-11 की ति-1 की तुलना में ति-2: 2010-11	2010-11 की ति-2 की तुलना में ति-3: 2010-11	2010-11 की ति-3 की तुलना में ति-4: 2010-11	2010-11 की ति-4 की तुलना में ति-1: 2011-12	2011-12 की ति-1 की तुलना में ति-2: 2011-12	2011-12 की ति-2 की तुलना में ति-3: 2011-12
1	2	3	4	5	6	7	8
कंपनियों की संख्या	2,352						
बिक्री	-4.5	5.9	5.7	12.9	-3.1	3.1	5.7
स्टॉक में परिवर्तन	100.0	-66.2	75.3	95.1	-47.7	-44.7	234.3
व्यय	-3.8	5.0	5.7	14.8	-3.6	4.9	7.6
जिसमें में कच्चा माल	-4.1	3.1	9.4	15.8	-2.3	1.6	8.4
स्टाफ लागत	3.2	8.1	2.1	5.2	3.6	5.8	3.4
ऊर्जा एवं ईंधन	11.6	1.0	4.4	7.6	12.3	-0.1	7.9
परिचालन लाभ (पीबीआईटी)	-2.1	0.8	8.8	8.6	-5.6	-11	3.1
अन्य आय*	-44.7	39.7	-24.2	44.7	-9.1	26.3	3.2
मूल्यहास	1.3	2.1	3.2	8.0	-3.6	2.1	3.6
सकल लाभ (पीबीआईटी)	-10.1	4.5	5.8	12.4	-6.5	-9.9	2.9
ब्याज	17.5	-2.7	7.7	6.6	9.4	18.7	2.7
कर प्रावधान	-11.9	4.4	2.0	9.0	4.8	-11.2	-4.0
निवल लाभ (पीएटी)	-10.3	5.6	3.4	16.1	-15.8	-16.3	-15.6

*अन्य आय में असामान्य आय/व्यय शामिल नहीं है, यदि वह सुनिश्चितता के साथ रिपोर्ट किया गया हो।

और II.6)। निवल लाभों में कुछ बड़ी कंपनियों के व्यापक गैर-परिचालन घाटे के कारण और कमी आई।

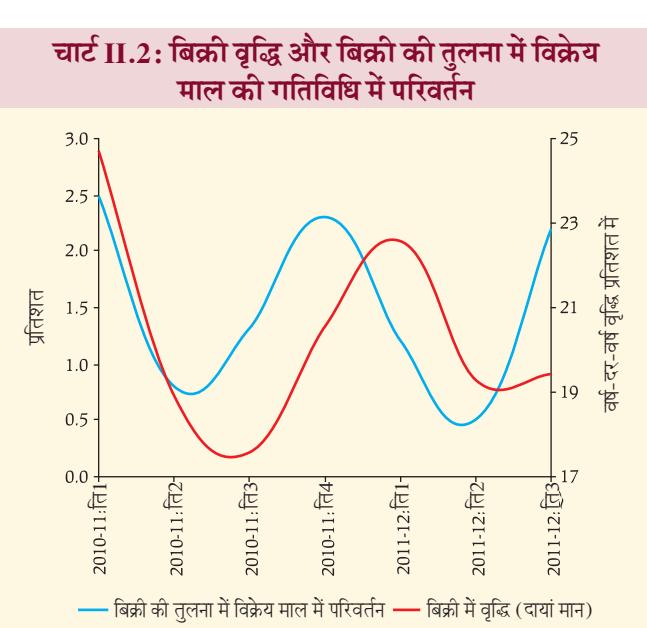
II.7 विक्रेय माल से बिक्रियों का अनुपात 2011-12 की ति3 में पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि और पूर्व तिमाही की तुलना में ऊँचा रहा (चार्ट II.2)। ति3 में इंवेंट्री का संचयन मुख्यरूप से रासायनिक

उर्वरकों और कीटनाशकों, लोहा और इस्पात, तेलशोधन और खाद्य उत्पादों और पेय उद्योगों में देखा गया।

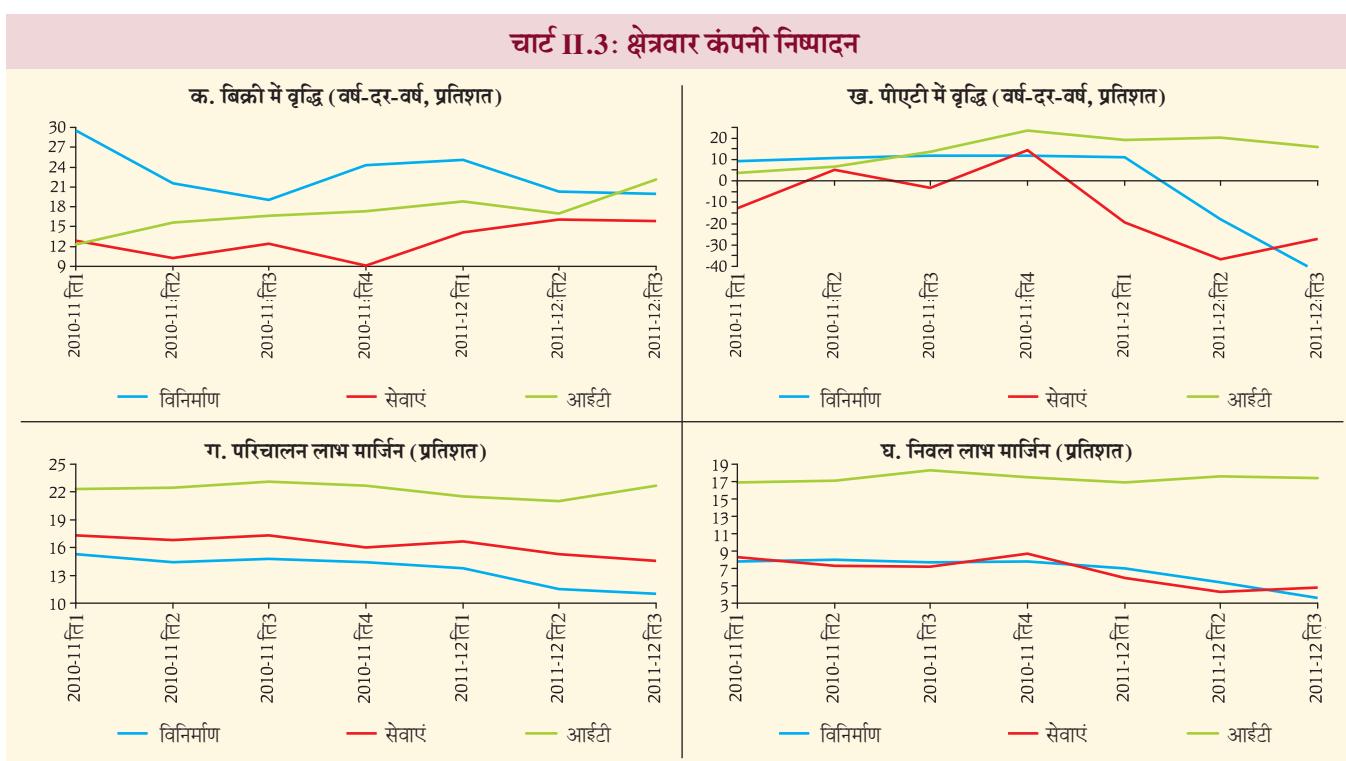
II.8 क्षेत्रवार विश्लेषण बतलाता है कि बिक्रियों और परिचालन लाभों के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सर्वोत्तम निष्पादक क्षेत्र रहा। अतः क्षेत्र का निवल लाभ मार्जिन अधिकांशतः ठीकठीक बना रहा (चार्ट-II.3) यह मुख्य रूप से रुपये का अवमूल्यन दर्शाता है। निविष्टि मूल्यों और ब्याज भुगतानों में उच्चतर वृद्धि से विनिर्माण और सेवा क्षेत्र, दोनों के लाभों में गिरावट आई।

2012-13 के बजट में राजकोषीय घाटे को उल्लेखनीय रूप से कम करने हेतु विश्वसनीय राजकोषीय समेकन रणनीति के सहारे की आवश्यकता है

II.9 केन्द्र सरकार अपने राजकोषीय घाटे को 2011-12 के बजट अनुमानों के अनुसार नियंत्रित नहीं कर पाई जिससे सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) - जीडीपी अनुपात 5.9 प्रतिशत तक बढ़ गया। किंतु, राजकोषीय स्थिति में 2012-13 में राजस्व घाटे और जीएफडी संकेतकों, दोनों के अनुसार उल्लेखनीय सुधार दर्ज होने का बजट बनाया गया है। संघीट बजट में राजकोषीय शुद्धिकरण का जैसा



चार्ट II.3: क्षेत्रवार कंपनी निष्पादन



सकेत दिया गया है और अन्य नीतिगत उपायों से जो कृषि, ऊर्जा और यातायात क्षेत्रों की आपूर्ति पक्षीय रुकावटों को हटाने के लिये किये जायेंगे, से अर्थव्यवस्था में निवेश गतिविधियों के पुनर्जीवित होने की स्थितियां पैदा होने की संभावना है।

II.10 इस बात को नोट किया जाय कि 2012-13 में प्रस्तावित राजकोषीय समेकन प्राथमिक रूप से केन्द्रीय सरकार के राजस्व बढ़ाने के उपायों पर आधारित है। जीएफडी - जीडीपी अनुपात में कमी के बजट प्रस्ताव की सफलता भी सरकार की सब्सिडी पर अपने व्यय को 2012-13 में जीडीपी के 2 प्रतिशत की तय की गई सीमा के भीतर रखने की प्रतिबद्धता पर निर्भर करेगी।

II.11 एफआरबीएम अधिनियम, 2003 के संशोधन और अधिनियम में मध्य-अवधि व्यय ढांचा विवरण जोड़े जाने, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, व्यय संकेतकों के मामले में तीन वर्षीय आवर्ती लक्ष्य शामिल होगा, से राजकोषीय अनुशासन आने की संभावना है। इससे सरकार के लिये आवश्यक राजकोषीय अवसर बनेगा जिससे उसे बारहवीं योजना के दौरान अपने तेजतर, स्थायी और अधिक समाहित कारक वृद्धि के उद्देश्य को बढ़ाने में सहायता मिलेगी। तथशुदा राजकोषीय शुद्धिकरण के बावजूद, मुख्य घाटा 13 वें वित्त आयोग द्वारा तय किये गये पथ से अधिक रहेगा (सारणी II.7)।

सारणी II.7: प्रमुख राजकोषीय संकेतक				
(जीडीपी का प्रतिशत)				
वर्ष	प्राथमिक घाटा	राजस्व घाटा	प्रभावी राजस्व घाटा	सकल राजकोषीय घाटा
1	2	3	4	5
केंद्र				
2009-10	3.2	5.2	—	6.5
2010-11	1.8	3.3	2.1	4.9
2011-12 ब अ	1.6	3.4	1.8	4.6
2011-12 स अ	2.8	4.4	2.9	5.9
2012-13 ब अ	1.9	3.4	1.8	5.1
13 वां वित्त आयोग	—	1.2	—	4.2
2013-14	—	2.8	1.0	4.5
चल लक्ष्य	—	0.0	—	3.0
13 वां वित्त आयोग	—	2.0	0.0	3.9
2014-15	—	-0.5	—	3.0
चल लक्ष्य	—	—	—	—
13 वां वित्त आयोग	—	—	—	—
राज्य*				
2009-10	1.2	0.5	—	2.9
2010-11 स अ	1.0	0.3	—	2.7
2011-12 ब अ	0.6	-0.2	—	2.2
संयुक्त				
2009-10	4.5	5.7	—	9.4
2010-11 स अ	3.4	3.8	—	8.1
2011-12 ब अ	2.5	3.2	—	7.0

ब अ : बजट अनुमान स अ : संशोधित अनुमान
* 28 राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों पर आधारित आंकड़े।
नोट : नकारात्मक चिह्न (-) घाटा संकेतकों में अधिक्य दर्शाता है।
स्रोत : 2012-13 का संघीय बजट और 13 वां वित्त आयोग।

2012-13 में कर वृद्धि से कर उपाय परिलक्षित होते हैं लेकिन अधोगामी जोखिमों की संभावना भी है

II.12 2011-12 की मंदी के साथ-साथ पहले शुरू किये गये कर परिवर्तनों के चलते, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों की कर राजस्वों में वर्ष के लिये प्रस्तावित दर के साथ-साथ 2010-11 की दर की अपेक्षा धीमी गति से वृद्धि हुई (सारणी II.8)। 2012-13 के संघीय बजट में घोषित किये गये कर उपायों, यथा, (छूट प्राप्त श्रेणियों की एक नकारात्मक सूची तय करके) सेवा कर के आधार को विस्तृत बनाना, मानक उत्पादन शुल्क और सेवा कर दरों में कटौतियों का आंशिक रूप से वापस लेना और सीमा शुल्क दरों को तर्कसंगत बनाना, के आधार पर 2012-13 के लिये करों में 1.39 के उछाल की संभावना है। यह 2003-04 से 2011-12 की अवधि के लिये 1.11 के दीर्घकालिक औसत कर उछाल के साथ ही हाल की अवधि 2010-11 से 2011-12 के औसत 1.14 से काफी उच्चतर है।

2012-13 के बाद से सब्सिडी व्यय को सीमित करने की प्रतिबद्धता एक सकारात्मक कदम

II.13 जैसाकि संघीय बजट 2012-13 में बताया गया है, 2011-12 में राजकोषीय संतुलन बिगड़ने का एक मुख्य कारण सब्सिडी व्यय का बहुत अधिक बढ़ जाना था, 2012-13 में व्यय की पुनर्रचना की रणनीति के मूल में सब्सिडी व्यय को सीमित करने के साथ पूँजी व्ययों (योजना और योजनेतर घटक, दोनों ही) के लिये विनियोजन को बढ़ाना है। आने वाले वर्षों में सब्सिडी पर व्यय को जीडीपी के 2 प्रतिशत से कम पर सीमित कर देना राजकोषीय समेकन की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि होगी।

II.14 2012-13 के लिये केन्द्र सरकार के वित्त में व्यय पक्ष पर अप्रकट दबाव है। पेट्रोलियम सब्सिडी के संदर्भ में पर ऊर्ध्वपक्षी जोखिम अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल के ऊँचे मूल्यों और विनियम दर पर दबावों के कारण उपजते हैं। जब तक सरकार वर्ष के प्रारंभिक भाग में निदेशित पेट्रोलियम उत्पादों के लचीले मूल्य-निर्धारण की ओर क्रमशः नहीं बढ़ती तब तक बजट अनुमानों पर पर्याप्त जोखिम बना रहेगा। यदि इन उत्पादों के मूल्यों को ऊपर की ओर समायोजित

सारणी II.8: केन्द्र सरकार के वित्त

मद	वृद्धि दर (प्रतिशत)			जीडीपी का प्रतिशत		
	2010-11	2011-12 सं अ	2012-13 ब अ	2010-11	2011-12 सं अ	2012-13 ब अ
1	2	3	4	5	6	7
1. कुल व्यय	16.9	10.1	13.1	15.6	14.8	14.7
2. राजस्व व्यय	14.1	11.6	10.7	13.6	13.0	12.7
3. पूँजी व्यय	39.0	0.1	30.6	2.0	1.8	2.0
4. विकास व्यय	7.3	15.4	16.1	7.2	7.1	7.3
5. विकास व्यय	26.1	6.8	9.2	8.7	8.0	7.6
4. योजनेतर व्यय	13.5	9.0	8.7	10.7	10.0	9.5
5. योजना व्यय	24.9	12.6	22.1	4.9	4.8	5.1
6. राजस्व प्राप्तियां	37.6	-2.7	22.0	10.3	8.6	9.2
i) कर राजस्व (निवल)	24.8	12.7	20.1	7.4	7.2	7.6
ii) करेतर राजस्व	88.0	-42.9	32.0	2.8	1.4	1.6
7. सकल कर राजस्व	27.0	13.7	19.5	10.3	10.1	10.6
i) प्रत्यक्ष कर	18.1	12.3	13.9	5.8	5.6	5.6
ii) अप्रत्यक्ष कर	40.5	15.5	26.5	4.5	4.5	5.0
ज्ञापन :						
8. राजस्व घाटा	-25.6	56.6	-11.3	3.3	4.4 (3.4)	3.4
9. प्रभावी राजस्व घाटा	-	56.3	-27.8	2.1	2.9 (1.8)	1.8
10. सकल राजकोषीय घाटा	-10.7	39.7	-1.6	4.9	5.9 (4.6)	5.1
11. सकल प्रारंभिक घाटा	-32.0	76.5	76.5	1.8	2.8 (1.6)	1.9

ब अ : बजट अनुमान

सं अ : संशोधित अनुमान

नोट : कोष्ठकों के दिये गये आंकड़े 2011-12 के लिये जीडीपी के प्रतिशत के रूप में बजट अनुमान हैं।

स्रोत : संघीय बजट 2012-13.

सारणी II.9 : कुल सब्सिडी

(राशि ₹ बिलियन में)

मद्दें	2010-11		2011-12 सं अ		2012-13 ब अ	
	राशि	जीडीपी का %	राशि	जीडीपी का %	राशि	जीडीपी का %
1	2	3	4	5	6	7
कुल सब्सिडी	1,734.2	2.3	2,163.0	2.4	1,900.2	1.9
जिसमें से						
i. खाद्य	638.4	0.8	728.2	0.8	750.0	0.7
ii. उर्वरक	623.0	0.8	672.0	0.8	609.7	0.6
iii. पेट्रोलियम	383.7	0.5	684.8	0.8	435.8	0.4
iv. ब्याज सब्सिडी	46.8	0.1	57.9	0.1	79.7	0.1
v. अन्य सब्सिडी	42.2	0.1	20.0	0.0	24.9	0.0

स्रोत : संघीय बजट 2012-13

नहीं किया गया तो 2012-13 में 2011-12 की अपेक्षा उगाहियों में गिरावट बहुत अधिक बढ़ सकती है। इससे व्यापक राजकोषीय फिसलन बढ़ेगी।

II.15 साथ ही, 2012-13 खाद्य सब्सिडियों में 3 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि को यदि खाद्य सुरक्षा बिल के कार्यान्वयन के संदर्भ में देखा जाय तो वह संतुलित प्रतीत होती है (सारणी II.9)।

राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के लिये बाजार क्रहणों पर बढ़ती निर्भरता ब्याज दरों पर दबाव बढ़ा सकती है

II.16 2012-13 के लिये राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण का स्वरूप बाजार क्रहणों पर सतत निर्भरता दर्शाता है, यद्यपि खजाना बिलों के माध्यम से अल्पकालिक वित्तपोषण के विकल्प का अनुमान 2 प्रतिशत है जो 2011-12 के 22 प्रतिशत से काफी कम है (सारणी II.10)। केन्द्र सरकार के व्यापक बाजार क्रहणों से प्रतिफलों पर दबाव बढ़ सकता है, विशेष कर दूर के छोर पर ऐसे दबाव काफी तीव्र बन सकते हैं, यदि वृद्धि में सुधार के साथ क्रहण मांग जोर पकड़े जो सरकार पर ब्याज भार बढ़ा दे और निजी निवेशों को कम कर दे।

अर्थव्यवस्था में सुधार विश्वसनीय राजकोषीय समेकन, मुद्रा-स्फीति नियंत्रण और उच्चतर पूँजी निर्माण पर टिका हुआ है

II.17 यद्यपि 2011-12 में निवेश खर्च कम हो गया, 2012-13 के दौरान धीमा सुधार शुरू हो सकता है। सुधार इस पर निर्भर करेगा कि मुद्रास्फीति पुनः गति न पकड़े। वर्तमान आकलन के अनुसार, निवेश धीमी गति से बढ़ना शुरू हो जाना चाहिये, विशेषतः पूँजी की लागत

सारणी II.10: सकल राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण का स्वरूप

(राशि ₹ बिलियन में)

मद	2011-12 (ब अ)	2011-12 (सं अ)	2012-13 (ब अ)
1	2	3	4
सकल राजकोषीय घाटा	4,128.2	5,219.8	5,135.9
निम्न द्वारा वित्तपोषित			
निवल बाजार ऋण *	3,531.3 (85.5)	4,843.0 (92.8)	4,930.0 (96.0)
लघु बचत (निवल)	241.8 (5.9)	-103.0 (-2.0)	12.0 (0.2)
बाब्य सहायता	145.0 (3.5)	103.1 (2.0)	101.5 (2.0)
राज्य भविष्य निधि	100.0 (2.4)	100.0 (1.9)	120.0 (2.3)
एनएसएसएफ	0.9 (0.0)	60.8 (1.2)	49.4 (1.0)
नकद निधि आहरण	200.0 (4.8)	-246.6 (-4.7)	-
अन्य	-90.9 (-2.2)	462.5 (8.9)	-77.0 (-1.5)

सं अ : संशोधित अनुमान ब अ : बजट अनुमान :- : शून्य

* केवल दिनांकित प्रतिभूतियां और 364 दिवसीय खजाना बिल समाप्ति

नोट : कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े जीएफडी की तुलना में प्रतिशतता दर्शाते हैं।

कम होने पर। किंतु, बैंकों के लिये लागत निधियों की कठोरताएं और घरेलू क्षेत्र के वित्तीय आधिक्य पर सरकार का व्यापक मसौदा, ब्याज दरों को स्थिरता प्रदान करता है।

II.18 भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2004-05 से शुरू हुई 4 वर्ष की अवधि के दौरान एक तर्कसंगत उपभोग-स्थिर निवेश मिश्रण बनाये रखा। किंतु, हाल के वर्षों में उपभोग घटक वृद्धि का प्रबल प्रेरक रहा है जिसमें स्थिर निवेश घटक के अंशादान में संकट-पूर्व (2005-08) के स्तरों से तीव्र गिरावट दिखाई दी है। निवेश की गति में धीमेपन से अर्थव्यवस्था का अंतर्भूत उत्पादन कम हो जाता है जिससे पुनर्सुलन का महत्व बढ़ जाता है। उच्च स्तरीय सरकारी खर्च से उपभोग को बल अवश्य मिलता है लेकिन स्फीतीय स्थिति भी जुड़ जाती है। कड़ी मौद्रिक नीति के द्वारा स्फीति से निकलना स्थाई वृद्धि और निवेश को बढ़ाने में महत्वपूर्ण बन पड़ता है, भले ही उससे अल्पकाल में पूँजी की लागत बढ़ती हो।

II.19 इस संदर्भ में, यह महत्वपूर्ण है कि अद्यतन बजट में यथालक्षित राजकोषीय समेकन जोखिमों के अधीन है, विशेषतया सब्सिडी के परिप्रेक्ष्य में। यदि आर्थिक वातावरण मंद बना रहा तो कर राजस्वों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। बजट में प्रस्तावित अप्रत्यक्ष कर उपाय स्वयं ही स्फीति के कारक बनेंगे। इस पृष्ठभूमि में समग्र मांग प्रबंधन 2012-13 के दौरान नीति के लिये चुनौतियां खड़ी करता है।